

सतना

20 अक्टूबर 2024
रविवार

दैनिक

मीडिया ऑडिटर



हरमनप्रीत न्यूजीलैंड...

सतना, रीवा से एक साथ प्रकाशित

@ पेज 7

संक्षिप्त समाचार

हरियाणा के पंचकुला में
खाई में गिरी स्कूल बस

15 बच्चे घायल

पंचकुला (एजेंसी)। हरियाणा के पंचकुला में शनिवार दोपहर पंचकुला से मोरनी हिल्स जा रही बच्चों से भरी स्कूल बस खाई में पलट गई। हादसे में बस के ड्राइवर के अलावा 10 से 15 बच्चे घायल हो गए। बच्चे स्कूल ट्रिप पर मोरनी हिल्स जा रहे थे। सभी बच्चों को मोरनी के



प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। गंभीर घायल बच्चों को पंचकुला के सेक्टर-6 स्थित अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। बस ड्राइवर विनोद खड्का के दोनों पैरों में फ्रैक्चर है। उन्हें चंडीगढ़ पीजीआई रेफर किया गया है। अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हादसा कैसे हुआ। पुलिस की टीम जांच कर रही है।

मणिपुर में उग्रवादियों
ने गांव पर बम फेंके

फायरिंग जारी

इम्फाल (एजेंसी)। मणिपुर के जिरिबाम जिले में एक बार फिर हिंसा भड़की है। बोरोबेकरा इलाके के एक गांव में उग्रवादियों ने शनिवार सुबह 5 बजे फायरिंग कर दी। बोरोबेकरा पुलिस ने बताया कि उग्रवादियों ने गांव में बम भी फेंके हैं। सूचना मिलने पर पुलिस और सीआरपीएफ



की टीम में मौके पर पहुंची है। उग्रवादियों और सुरक्षाबलों के बीच फायरिंग लगातार जारी है। फिलहाल हमले में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। पुलिस ने बताया कि बोरोबेकरा जिरिबाम टाउन से 30 किमी दूर है। इस इलाके में घने जंगल और पहाड़ हैं और यहां पहले भी गोलीबारी हो चुकी है।

जम्मू-कश्मीर के पुंछ में
दो आतंकी गिरफ्तार

3 ग्रेनेड और 1 पिस्तौल भी बरामद

श्रीनगर (एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर के पुंछ में शनिवार सुबह सुरक्षाबलों ने 2 आतंकीयों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 3 ग्रेनेड और 1 पिस्तौल भी बरामद की गई है। सेना के अधिकारियों ने बताया ये दोनों जम्मू-कश्मीर गजनी फोर्स नाम के संगठन से जुड़े हाइड्रिड आतंकी हैं। हाइड्रिड आतंकी आम नागरिकों



की तरह ही इलाके में रहते हैं, लेकिन घोरी-छिपे आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होते हैं या आतंकीयों की सहायता करते हैं। इन्हें पहचानना मुश्किल हो जाता है। जम्मू पुलिस के डीसीपी आनंद जैन ने कहा कि पूछताछ में पता चला कि दोनों आतंकी ने मदिरा, सेना के ठिकानों और एक अस्पताल पर ग्रेनेड फेंकने की प्लानिंग कर रहे थे।

हिंसा के बाद बुलडोजर
एक्शन की हो गई तैयारी

बहराइच के 23 घरों पर रातोंरात चिपकाया अतिक्रमण का नोटिस

सीएम योगी को एसटीएफ चीफ ने बताए क्षेत्र के हालात

बहराइच (एजेंसी)। बहराइच हिंसा का शनिवार को 7वां दिन है। सड़कों पर अभी भी सनाटा है। जगह-जगह फोर्स तैनात है। हालांकि, अब प्रशासन एक्शन में जुट गया। राम गोपाल की हत्या में मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद के घर पर बुलडोजर चल सकता है। इसी घर में भगवा झंडा लहराने के दौरान राम गोपाल को गोली मारी गई थी।

शुक्रवार रात को पीडब्ल्यूडी की ओर से महाराजगंज में 23 मकानों पर नोटिस चप्पा किए गए हैं। इनमें 20 मुस्लिम



और 3 हिंदुओं के मकान हैं। प्रशासन ने 3 दिन का वक्त दिया है। नोटिस का जवाब मिलने पर बुलडोजर कार्रवाई हो सकती है। यह वही जगह है जहां से मूर्ति विसर्जन के दौरान हिंसा की शुरुआत हुई थी। हालांकि, पीडब्ल्यूडी ने एक बयान जारी कहा- महाराजगंज में पहले भी अतिक्रमण हटाय गया था। दोबारा रोड किनारे अतिक्रमण हो गया। इसे हटाने पर बुलडोजर नोटिस चप्पा किए गए हैं, उनमें हिंसा के आरोपियों में एक नाम है।

जम्मू-कश्मीर को स्टेटहुड के प्रस्ताव को एलजी की मंजूरी

उमर दो दिन में पीएम मोदी से मिलेंगे, डिप्टी सीएम बोले-केंद्र वादा पूरा करें

श्रीनगर (एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के प्रस्ताव को उपराज्यपाल ने शनिवार को मंजूरी दे दी। गुरुवार को राज्य के दर्जे की बहाली के लिए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट ने प्रस्ताव पास किया था। डिप्टी सीएम सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा, केंद्र को अपना वादा पूरा करना चाहिए और राज्य का दर्जा बहाल करना चाहिए, यह हमारा अधिकार है। हम वही मांग रहे हैं जो उन्होंने पहले ही वादा किया था। इस मांग को लेकर उमर अब्दुल्ला 2 दिन में दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। दरअसल, केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के साथ ही प्रदेश का पूर्ण राज्य का दर्जा खत्म करते हुए उसे दो यूनिवर्सल टेरिटरी (जम्मू-कश्मीर और लद्दाख) में बांट दिया था। उमर ने



विधानसभा चुनाव के दौरान भी कहा था कि कैबिनेट की पहली मीटिंग में ही जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने के प्रस्ताव को मंजूर किया जाएगा। 16

अक्टूबर को सीएम पद की शपथ लेने के बाद अगले दिन ही उन्होंने प्रस्ताव पास किया। कैबिनेट की मीटिंग में डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी, मंत्री सकीना मसूद इट्टा, जावेद अहमद राणा, जाविद अहमद डार और सतीश शर्मा भी मौजूद थे। पीडीपी ने उमर कैबिनेट के फैसले को लेकर कहा कि यह हमारे लिए बड़ा झटका है। उमर सरकार ने स्टेटहुड बहाली का प्रस्ताव क्यों पारित किया। 370 की बहाली पर भी फैसला करना चाहिए था। पीडीपी के विधायक वहीद परान ने शुक्रवार को कहा- उमर अब्दुल्ला का राज्य के दर्जे पर प्रस्ताव पारित करना 5 अगस्त, 2019 के केंद्र के फैसले का सम्मर्थन करने से कम नहीं है। उमर ने 370 को बहाल करने के वादे पर ही वोट मांगे थे। प्रस्ताव को उपराज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।

झारखंड में 70 सीटों
पर मिलकर लड़ेगी
कांग्रेस-जेएमएम

राजद को 7 सीटें, 4 पर फैसला नहीं



रांची (एजेंसी)। कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर सहमति बन गई है। सीएम हेमंत सोरेन और कांग्रेस के झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर सहित कई नेताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की घोषणा की। उन्होंने कहा- कांग्रेस और जेएमएम 70 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ेगी, बाकी बची सीटों के लिए जल्द ही जानकारी साझा की जाएगी। सीएम हेमंत सोरेन ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा- अन्य सीटों के लिए मंथन किया जाएगा। हमारे साथ वाम दल भी जुड़ रहे हैं उनके साथ भी सीट साझा की जाएगी। राजद को 7 सीटें देने पर सहमति बनी है। होटल रेडिसन ब्लू में राजद की बैठक चल रही है। मीटिंग खत्म होने के बाद उनका पक्ष क्या आता है, इसके बाद आगे की बात सामने आएगी। कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी आज झारखंड दौर हैं। वे रांची एयरपोर्ट से सीधे रेडिसन ब्लू होटल पहुंचे हैं।

खाड़ी देशों में तेरह हजार
पीएफआई मैसेज हैं ऐक्टिव

इंडी का आरोप-इन्हें करोड़ों के फंड जुटाने का है टारगेट

भारत में आतंकीयों तक हवाला से पहुंचाई जा रही रकम

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत में प्रतिबंधित संगठन पापुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के खिलाफ 2 साल से चल रही इंडी की जांच में नए खुलासे हुए हैं। इंडी ने शुक्रवार को बताया कि पीएफआई के सिंगापुर और खाड़ी देशों में 13 हजार से ज्यादा ऐक्टिव मैसेज हैं, जिन्हें करोड़ों रुपए के फंड जुटाने की जिम्मेदारी मिली हुई है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक, पीएफआई ने खाड़ी देशों में रह रहे प्रवासी मुस्लिम समुदाय के लिए डिस्ट्रिक्ट एजीक्यूटिव कमेटियां बनाई हैं। इन्हें कमेटियों को फंड जुटाने की जिम्मेदारियां दी गई थीं। इंडी ने बताया कि विदेशों से जुटाए करोड़ों



के फंड को अलग-अलग बैंक खातों में जमा किया जा रहा है। यह फंड भारत में बैठे पीएफआई के अधिकारियों और आतंकीयों तक आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए पहुंचाया जाता था। सितंबर 2022 में देशभर में पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए और इंडी ने छापे मारा था। इसमें पीएफआई से जुड़े कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। इन पर यूएफए के तहत कार्रवाई की गई थी। छापेमारी के बाद केंद्र सरकार ने 2022 से पीएफआई संगठन को बंद कर दिया था। इंडी तब से पीएफआई के खिलाफ जांच कर रही है।

राहुल बोले, महिलाएं दफतरो
में अब सिम्बॉलिक पद न लें

● उन्हें अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, आजकल सिर्फ विचारधाराओं की लड़ाई होती है

नई दिल्ली (एजेंसी)। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को दिल्ली में शक्ति अभियान की मीटिंग में महिलाओं से कहा कि महिलाओं को ऑफिस में केवल को महिला संख्या दिखाने वाले सिम्बॉलिक पद स्वीकार नहीं करने चाहिए। उन्हें अपने हक के लिए लड़ना चाहिए और बड़े पदों की मांग करनी चाहिए। राहुल ने महिलाओं से कहा कि आज की राजनीति में केवल पॉलिटिकल पार्टियों की ही लड़ाई नहीं होती है, बल्कि आज की राजनीति अलग-अलग विचारधाराओं की लड़ाई बन गई है। उन्होंने कहा कि आज राजनीति में लड़ाई सिर्फ सत्ता के लिए नहीं बल्कि लीडरशिप के लिए भी है। दरअसल, शक्ति अभियान महिलाओं का एक संगठन है। इसमें अलग-अलग क्षेत्र में अच्छे प्रदर्शन करने वाली महिलाएं शामिल होती हैं। यह मीटिंग शनिवार और रविवार को भी जारी रहेगी। राहुल बोले- मैं महिलाओं के अधिकारों के साथ हूँ राहुल ने मीटिंग में कहा कि इंदिरा फेलोशिप जमीनी स्तर की महिला नेताओं के एक मजबूत नेटवर्क को खड़ा करने में मदद कर रहा है।

हिजबुल्लाह ने नेतन्याहू
के निजी आवास पर
किया ड्रोन अटैक

आईडीएफ बोला-

होम टाउन सिसेरिया में हमला, इजराइली
पीएम और परिवार मौजूद नहीं था

तेल अवीव (एजेंसी)। हिजबुल्लाह ने शनिवार को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के होम टाउन सिसेरिया में ड्रोन अटैक किया। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक, आईडीएफ ने हमले की पुष्टि की है। आईडीएफ ने कहा कि इस ड्रोन अटैक में पीएम नेतन्याहू का निजी आवास निशाने पर था। हमले के वक्त नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा घर पर नहीं थे। ड्रोन सिसेरिया की एक इमारत पर गिरा। कोई हताहत नहीं हुआ है। इजराइली डिफेंस फोर्स ने कहा कि शनिवार को लेबनान से इजराइल पर 3 ड्रोन दगे गए।



इजराइली फोर्स ने 2 ड्रोन को मार गिराया। अटैक के बाद गिलोत सैन्य अड्डे पर अलार्म बजने लगे। आईडीएफ ने माना है कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम हमले को रोकने में विफल रहा। उन्होंने कहा कि वे ड्रोन घुसपैठ की जांच कर रहे हैं। आईडीएफ ने कहा कि पिछले एक घंटे में (भारतीय समय से दोपहर 1 से 2 बजे के बीच) लेबनान से उत्तरी इजराइल पर लगभग 55 रॉकेट दगे गए हैं। कुछ को रोक लिया गया है जबकि कई खुले इलाके में गिरे हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक हमले में कम से कम 9 लोग घायल हुए हैं। इजराइली हमले में हमला सीएम सिनवार की मौत के बाद पहली बार इरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई का बयान आया है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक उन्होंने कहा है कि याह्या सिनवार की मौत के बाद भी हमला खत्म नहीं हुआ है। सिनवार अपने शहीद दोस्तों के पास चले गए हैं।

6 दिन में अब तक 50 से ज्यादा विमानों में
बम की धमकियां, 80 करोड़ का नुकसान

नई दिल्ली (एजेंसी)। इंडियन एयरलाइंस की 30 से ज्यादा फ्लाइट में शनिवार को बम होने की धमकी मिली। इसमें इंडिगो, एअर इंडिया, अकासा, विस्तारा, स्प्राइजेट, स्टार एयर और एलायंस एयर शामिल हैं। पिछले एक हफ्ते में 50 से ज्यादा विमानों को बम की धमकी मिल चुकी है, ये सभी झूठी साबित हुईं। इन धमकियों की वजह से एयरलाइंस को अब तक 80 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। लगातार मिल रही धमकियों के बीच केंद्र सरकार ने 16 अक्टूबर को फ्लाइट्स में एयर मार्शलों की संख्या को दोगुना करने का फैसला किया था। गृह मंत्रालय ने भी एविएशन मिनिस्ट्री से रिपोर्ट मांगी है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक, इंडिगो की 3 फ्लाइट्स को बम की धमकी मिली



है। इसमें दिल्ली और मुंबई से इस्तांबुल जा रही इंडिगो भी शामिल हैं। इसके अलावा विस्तारा की उदयपुर से मुंबई जाने वाले विमान को भी धमकी मिली थी। इन सभी विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। हालांकि, शनिवार को 20 से

ज्यादा विमानों को धमकी मिली है, लेकिन सभी की डिटेल्ड सामने नहीं आई है। लंदन और दुबई जा रही फ्लाइट में बम की धमकी शुक्रवार की देर रात एअर इंडिया एक्सप्रेस और विस्तारा एयरलाइंस की एक-एक फ्लाइट में बम होने की धमकी दी गई। इनमें से दिल्ली से लंदन जा रही विस्तारा की फ्लाइट को फ्रैंकफर्ट डायवर्ट किया गया। जबकि 189 पैसेजर्स को लेकर दुबई जयपुर आ रही एअर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान की जयपुर में रात 12:40 बजे इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। जांच में दोनों ही विमानों में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। मुंबई पुलिस ने एक को अरेस्ट किया मुंबई की पुलिस ने फ्लाइट में बम रखने की झूठी खबर फैलाने के मामले में एक को गिरफ्तार किया है।

शनिवार को 15 फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की मिली धमकी

नई दिल्ली (एजेंसी)। इंडिगो, एअर इंडिया और अकासा की 15 फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। यह आंकड़ा सिर्फ शनिवार का है। इस वजह से कई फ्लाइट्स की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी है। पिछले कई दिनों से कई विमानों को ऐसी ही धमकियां लगातार मिल रही हैं, केंद्र ने भी अपने स्तर पर जांच शुरू कर दी है। लेकिन आज शनिवार को बड़े स्तर पर कई एयरलाइंस को ऐसी धमकी जिस वजह से हड़कंप मच गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिगो को उसकी पांच इटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए धमकी मिली है जिसमें कई नंबर शामिल हैं। एयरलाइन ने एक जारी बयान में कहा है कि वो हर जरूरी कदम उठाएगी और अधिकारियों से लगातार संपर्क साध रही है। जानकारी तो यह भी मिली है कि इंडिगो की 6 ए 17 फ्लाइट मुंबई से इस्तांबुल जा रही थी। वहीं 6 ए 184 फ्लाइट जोधपुर से दिल्ली के लिए निकली थी। लेकिन दोनों ही विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है।

सीईओ जिला पंचायत ने रामपुरनैकिन में विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की

निर्माणधीन कार्यों का अवलोकन कर आवश्यक सुधार के लिए निर्देश

योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही और अनियमितता पर होगी कठोर कार्यवाही- सीईओ जिला पंचायत

मीडिया ऑडिटर, सीधी निप्र। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सीधी अंशुमन राज द्वारा शुक्रवार 18 अक्टूबर को सामुदायिक भवन रामपुर नैकिन के सभागार में पंचायत एवं ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। समीक्षा बैठक में जनपद पंचायत रामपुर नैकिन के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, परियोजना अधिकारी मनरेगा एवं आवास, सहायक यंत्री मनरेगा, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा, ब्लाक समन्वयक आवास एवं एस.बी.एम. पी.सी.ओ., उपयंत्री तथा समस्त ग्राम पंचायतों के सचिव तथा ग्र.रो. सहा. उपस्थित रहे। समीक्षा बैठक के दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा मनरेगा योजनागत माह अक्टूबर 2024 तक के लक्ष्य के विरुद्ध मानव दिवस सुजन, एसटी, एमसी परिवारों तथा महिला श्रमिकों को 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराने की समीक्षा करते हुए मानव दिवस सुजन के लक्ष्य के सापेक्ष न्यून प्रगति पर



नाराजगी व्यक्त की गई एवं लक्ष्य पूर्ति किये जाने हेतु कार्य करने के लिए निर्देशित किया गया। मनरेगा योजना से निर्माणधीन गोशालाओं एवं अपूर्ण आंगनवाड़ी भवनों की समीक्षा के दौरान क्रियान्वयन एजेंसी आर.ई.एस., ग्राम पंचायत की कार्यपालनी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराने तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 तथा उसके पूर्व के कार्यों की पूर्णता हेतु उपयंत्रियों एवं सचिव/ग्रामरोजगार सहायकों को समयावधि में कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये।

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत प्रदत्त लक्ष्य के

सापेक्ष प्रगति, पी.एम. जनमन आवास पूर्णता एवं अपूर्ण आवास निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी ग्राम पंचायत भवनों की बाहरी दीवार पर ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभाभित हितग्राहियों एवं प्रतीक्षा सूची के हितग्राहियों के नामों को स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया जाये। साथ ही पंचायत समन्वयक अधिकारियों को उनके कलस्टर की ग्राम पंचायतों के लिए आवास योजना का नोडल अधिकारी बनाया जाये।

समीक्षा बैठक के दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा स्वच्छ

भारत मिशन, एस.आर.एल.एम., तथा सम्बल योजना की प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा उपस्थित अधिकारी कर्मचारियों को शासन की गाईड लाइन का पालन करते हुए समस्त योजनाओं में प्रगति करने तथा योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही व अनियमितता नहीं करने के निर्देश दिये गये।

भरतपुर हैण्डलूम क्राफ्ट का क्रिया निरीक्षण: समीक्षा बैठक के उपरांत मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत कपुरी कोठार में मनरेगा एवं अन्य योजनाओं के अभिसरण से निर्मित तालाब निर्माण कार्य का एवं अन्य कार्यों का अवलोकन किया गया। इसके साथ ही चंदेरे स्थित ऐतिहासिक शिव मंदिर में दर्शन उपरांत सामुदायिक स्वच्छता परिसर चंदेरे का निरीक्षण किया गया, स्वच्छता परिसर में साफ



निरीक्षण किया गया। उनके द्वारा प्रभारी अधिकारी से संचालित की जाने वाली गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की गई।

निर्माण कार्यों का क्रिया अवलोकन: समीक्षा बैठक के उपरांत मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत कपुरी कोठार में मनरेगा एवं अन्य योजनाओं के अभिसरण से निर्मित तालाब निर्माण कार्य का एवं अन्य कार्यों का अवलोकन किया गया। इसके साथ ही चंदेरे स्थित ऐतिहासिक शिव मंदिर में दर्शन उपरांत सामुदायिक स्वच्छता परिसर चंदेरे का निरीक्षण किया गया, स्वच्छता परिसर में साफ

सफाई तथा पानी की समुचित व्यवस्था न होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए ग्राम पंचायत चंदेरे के सचिव/ग्राम रोजगार सहायक को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये जाने के निर्देश दिये गये। इसके पश्चात ग्राम पंचायत झगरी के कनकटी ग्राम में मनरेगा योजना से निर्माणधीन तालाब, गोशाला एवं पंद्रहवां वित्त से निर्मित चबूतरा निर्माण कार्य का अवलोकन किया गया। गोशाला निर्माण कार्य में कमियां पाये जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्माण एजेंसी आर.ई.एस. के उपयंत्री को आवश्यक सुधार किये जाने के निर्देश दिये गये।

शासकीय महाविद्यालय मड़वास में दो दिवसीय युवा उत्सव कार्यक्रम सम्पन्न



मीडिया ऑडिटर, सीधी निप्र। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार शासकीय महाविद्यालय मड़वास में दो दिवसीय युवा उत्सव का आयोजन किया गया। प्रतिवर्ष उच्च शिक्षा विभाग द्वारा छात्र-छात्राओं को कला मंच प्रदान करने के उद्देश्य से युवा उत्सव का आयोजन किया जाता है। कार्यक्रम का उद्घाटन महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. आई.पी.प्रजापति के द्वारा किया गया। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित छात्र-छात्राओं से कहा कि युवा उत्सव छात्रों को अपनी प्रतिभा को प्रस्तुत करने का बेहतर मंच होता है जहाँ पर उन्हें अपनी प्रतिभा को निखारने का अवसर मिलता है।

युवा उत्सव के दो दिवसीय आयोजन के सम्बंध में संयोजक डॉ. दीपक अग्निहोत्री ने बताया कि दो दिवसीय आयोजन में रूपांकन, साहित्यिक, सांस्कृतिक और सांगीतिक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें सॉर्ट पेंटिंग, पोस्टर, परिचर्चा, रंगोली, क्ले मॉडलिंग, वाद-विवाद, एकल/रुसमूह नृत्य, एकल/समूह गायन आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिसमें महाविद्यालय के छात्र- छात्राओं ने बड़ चढ़ कर हिस्सा लिया। दो दिवसीय आयोजन में आभार प्रदर्शन डॉ. निशा सिंह ने किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से डॉ. सोरभी गुप्ता, डॉ. संध्या वर्मा, डॉ. ज्योति रजक, डॉ. संगीता मिश्रा, डॉ. अमिता खरे, दीपराज प्रजापति, प्रवीण साकेत, डॉ. राजेश पटेल, डॉ. कमलेश जायसवाल, डॉ. अनुराग तिवारी, डॉ. पंकज मिश्रा, डॉ. सुरेंद्र गुप्ता, डॉ. लक्ष्मीकांत कुशवाहा, अनिल केवट सहित महाविद्यालय के छात्र-छात्रा उपस्थित रहे।

प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस जिला स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता में बनी विजेता



मीडिया ऑडिटर, सीधी निप्र। उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार 'प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस' संजय गांधी स्मृति शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय सीधी में जिला स्तरीय पुरुष टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन दिनांक 18-10-2024 को किया गया। इस प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री कॉलेज आफ एक्सीलेंस संजय गांधी महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. पी. के सिंह ने अपने उद्घाटन में खिलाड़ियों को खेल भावना से खेलने की सीख देते हुए खेल को जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने की बात कही। प्राचार्य ने कहा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खेल आज के जीवन शैली में बहुत ही आवश्यक है।

प्रतियोगिता में शासकीय पीजी कॉलेज बड़ैन एवं शासकीय संजय गांधी स्मृति महाविद्यालय सीधी के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। दोनों टीमों के बीच एक दूसरे के बीच खेले गए जिसमें सीधी की टीम तीनों मैच जीतकर विजेता बनी। संजय गांधी महाविद्यालय से अंबुज प्रताप सिंह, अतुल तिवारी, प्रशांत तिवारी, चंद्रकांत सिंह का चयन संभागीय स्तरीय पुरुष टेबल टेनिस प्रतियोगिता के लिए हुआ है जिसका आयोजन रीवा में होगा। इस प्रतियोगिता में आई टीमों के साथ उनके कोच मैनेजर तथा संजय गांधी स्मृति महाविद्यालय से डॉ. प्रभाकर सिंह, डॉ. रावेंद्र बाबुदर सिंह, डॉ. हरिचरण अहिंत्वार, सहायक प्राध्यापक कुसमी एवं रेफ्री आदित्य पटेल उपस्थित रहे। संपूर्ण प्रतियोगिता संजय गांधी महाविद्यालय के क्रीड़ा अधिकारी डॉ. रविंद्र नाथ सिंह की देखरेख में संपन्न हुई। उन्होंने ही इस प्रतियोगिता का सफल संचालन किया।

पिपरिया बांध के बैकवॉटर में 2 युवक डूबे जिस जाल से मछली पकड़ने गए थे, उसमें ही फंसकर हुई मौत



मीडिया ऑडिटर, अनूपपुर निप्र। पिपरिया बांध के बैकवॉटर में दो युवक जिस जाल से मछली पकड़ने गए थे, उसी में फंसकर डूब गए, जिससे उनकी मौत हो गई। घटना अनूपपुर के कोतमा में 18 अक्टूबर की है। शनिवार को स्टेट डिजास्टर इमरजेंसी रिस्पांस फोर्स यानी एसडीआरएफ की टीम ने दोनों के शवों को बाहर निकाला। पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए कोतमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा है। मृतकों की पहचान जोगीटोला में रहने वाले 25 वर्षीय तुलसी केवट और 23 वर्षीय कृष्णपाल गौड़ के रूप में हुई है। दोनों ने बांध से जुड़े निकासी टनल के पास जाल बिछा रखा था। शाम को जब दोनों घर नहीं पहुंचे तो परिजनों ने ढूंढना शुरू किया। बांध के टनल के किनारे इनके कपड़े और मोबाइल मिले, जिसके बाद डायल 100 को सूचना दी गई।

एसडीआरएफ की टीम ने निकाले शव: एसडीओपी सुमित केरकेट्टा ने बताया कि शुक्रवार रात कोतमा पुलिस घटना स्थल पहुंची और शहडोल की एसडीआरएफ टीम को सूचना दी। देर रात तक टीम ने युवकों की तलाश की, पर कहीं पता नहीं चला। शनिवार सुबह फिर से दोनों की तलाश शुरू हुई तो इनके शव जाल में फंसे मिले। घटना स्थल पर पहुंचे कोतमा तहसीलदार ईश्वर प्रधान, थाना प्रभारी सुंदरेश मरावी की मौजूदगी में शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए कोतमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया।

पटाखों के अवैध स्टोरेज पर प्रशासन की छापामार कार्रवाई 2 लाख से ज्यादा के पटाखे जब्त, दीपावली के लिए रिहायशी इलाके में रखे गए थे

मीडिया ऑडिटर, छतरपुर निप्र। जिला प्रशासन ने शनिवार शाम चार बजे पटाखों के अवैध स्टोरेज पर छापेमारी की। प्रशासन को रिहायशी इलाके में पटाखों का भंडार होने की सूचना मिली थी। जिसके बाद यह कार्रवाई की गई।

जानकारी के मुताबिक छत्रसाल नगर में आदित्य निगम के मकान में दीपावली के त्योहार को लेकर अवैध तरीके से पटाखे का भंडारण किया गया था। जहां प्रशासन ने छापेमारी कार्रवाई करते हुए आदित्य निगम के मकान से 2 लाख से अधिक के पटाखे जब्त किए हैं।

नदी में डूबने से एक बच्चे की मौत सीधी के ग्राम खुटेली में हादसा, चार दोस्त गए थे नहाने



मीडिया ऑडिटर, सीधी निप्र। सीधी के ग्राम खुटेली में शनिवार सुबह गोपद नदी में नहाने गए चार बच्चों में से एक की मौत हो गई। नहाते समय 13 वर्षीय सौरव पांडे गहरे पानी में चला गया था। जहां सांस भर जाने से वो डूब गया।

ग्रामवासियों ने नदी से निकाला शव: ग्रामवासी रामलाल विभवकर्मा ने बताया शनिवार सुबह चार दोस्त सौरव पांडे, सोनू, सफ़ीक मोहम्मद और रफीक मोहम्मद गोपद नदी में नहाने गए थे। चारों तैरते-तैरते गहरे पानी में पहुंच

गए। तीन दोस्त तो वापस आ गए पर सौरव थकान के कारण वहीं डूबने लगा। जिसे देख कर तीनों ने गांव वालों को बुलाया पर तब तक सौरव डूब चुका था। जिसके बाद ग्रामवासियों ने उसका शव निकाल पोस्टमॉर्टम के लिए बहरी अस्पताल भेजा।

पुलिस ने शुरु की जांच: वहीं बहरी थाना प्रभारी राकेश बैस का कहना है कि 13 वर्षीय बच्चे की गोपद नदी में डूबने से मौत हो गई है। फिलहाल मर्ग कायम कर जांच की जा रही है।

मैहर जिले के एसडीएम ने मां शारदा धाम का बनाया गान, पूरे प्रदेश में उनकी और उनके गान की हो रही चर्चा



मीडिया ऑडिटर, मैहर निप्र। मध्य प्रदेश गान की तर्ज पर मैहर में पदस्थ एसडीएम ने मैहर गान की रचना कर डाली। एसडीएम ने न केवल गान की रचना की, बल्कि कलेक्टर को गान भी सुनाया। मैहर गान में मां शारदा धाम मैहर जिले में स्थापित ऐतिहासिक धरोहरों और प्राचीन स्थलों को भी शामिल किया गया है। मैहर गान को सुनकर अब हर कोई उनकी सराहना कर रहा है।

व्यो खास है मां शारदा गान: आरती यादव मैहर जिले के अमरपाटन में एसडीएम पद पर पदस्थ हैं। उन्होंने एक रचना की जिसको उन्होंने मां शारदा को समर्पित किया है। मैहर गान हृदय के अंत गहराइयों से शारदा माता के प्रति श्रद्धा भाव अर्पित करती यह रचना अपने अंतर्मन में

जिले भर के प्रसिद्ध स्थलों के दर्शन कराती है। महर्षि मार्कण्डेय के तपोस्थली में बने आश्रम से मिलने वाली शांति आत्मा से परमात्मा का मिलन कराती है और उससे लगे बाणसागर बांध से मिलने वाली बिजली और पानी से अन्य प्रदेशों को शीतलता का अहसास कराने का जिज्ञ

रचना में किया गया है। हर कोई कर रहा गीत की तारीफ: अमरपाटन अनुभाग मजिस्ट्रेट ने अपने कार्यालयीन दायित्वों के साथ-साथ अपनी कलम से मां शारदा की भक्ति की अनुटी मिसाल पेश की है। वाणी और अंतरात्मा को माता शारदा के श्री चरणों में समर्पित किया है। जिले की मुखिया रानी बाटंड ने भी मैहर के गौरव दिवस पर अंतराष्ट्रीय स्तर पर मैहर का नाम रोशन कर बैटियों का मान बढ़ाया है। मैहर जिले में पदस्थ महिला अधिकारियों ने कार्यालय की सीमाओं से परे अपने मन, कर्म और वाणी से मैहर को अपनी कर्मस्थली माना है।

पुलिस ने निकाली हेलमेट बाइक रैली सड़क सुरक्षा को लेकर किया जागरूक, नगर के कई स्थलों पर दिखाए वीडियो क्लिप

मीडिया ऑडिटर, सिंगरोली निप्र। पुलिस अधीक्षक जिला सिंगरोली निवेदिता गुप्ता (भा.सू.से) के कुशल मार्गदर्शन और शिव कुमार वर्मा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिंगरोली के पर्यवेक्षण में सिंगरोली पुलिस ने हेलमेट बाइक रैली का आयोजन किया।

शनिवार शाम 4 बजे पुलिस सिंगरोली ने हेलमेट बाइक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें हेलमेट बाइक रैली पुलिस अधीक्षक कार्यालय से प्रारंभ होकर महाजन मोड़, रिलायंस तिराहा, कॉलेज तिराहा, पुराना यातायात तिराहा, मस्जिद तिराहा से होते हुए इंदिरा चौक होते हुए समाप्त हुई। इस रैली



में जिले के समस्त थानों के पुलिस बल शामिल हुआ। साथ ही यातायात पुलिस द्वारा

सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए यातायात जागरूकता के तहत मारुति वैन से शहर के विभिन्न

28 सूत्रीय मांगों को लेकर सरपंच संघ पहुंचा कलेक्टर सीधी में राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को सौंपा जापन, 8 बिंदुओं को लेकर रखी मांग

मीडिया ऑडिटर, सीधी निप्र। सीधी जिले में शनिवार को सरपंच संघ के जिलाध्यक्ष गणेश सिंह के नेतृत्व में करीब 50 सरपंचों ने अपनी 28 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर मुख्यालय पहुंचे। जहां महामहिम राष्ट्रपति के नाम गोपदबनास तहसीलदार जाह्नवी शुक्ला को मांग पत्र सौंपा है। जापन में सरपंच संघ ने 8 बिंदुओं को लेकर मांग रखी।

तहसीलदार को इन बिंदुओं पर जापन सौंपा गया:- 1- मनरेगा को मूल रूप में लाये जाने के लिये केंद्र सरकार से सहयोग की आवश्यकता है जिससे अधो-संरचना के छोटे मोटे काम स्वतंत्र रूप से कर सके। 2- मजदूरों को तत्काल मजदूरी भुगतान उपलब्ध करा सके, फसल शेड, पशु शेड, मुर्गी शेड, बकरी शेड और सुअर पालन शेड को मनरेगा से



जोड़कर निर्माण काम कराए जाएं। जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके। 3- ग्राम पंचायत विकास निधि गठित कर सरपंच निधि बनाई जाए। 4- सरपंच उपसरपंचों का 20

लाख का जीवन बीमा और न्यूनतम पेंशन 2 हजार किया जाए। 5- पंचायतों के अधिकतम कार्य की सीमा 20 को हटाया जाए। 6- प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास जल्दतमदद को ग्राम सभा के



अनुमोदन पर दिया जाए। 7- सरपंचों का मानदेय 20 हजार प्रतिमाह दिया जाए। 8- जेम पोर्टल को बंद कर पूर्व की व्यवस्था को दोबारा शुरू किया जाय।

मांग पत्र सौंपने के दौरान सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष गणेश सिंह चौहान के अलावा सरपंच पडरी निर्मला श्याम सुंदर सिंह, पड़ैनिया सरपंच अश्विनी सिंह परिहार, सरपंच पडखुरी रामसिया यादव, खान्द

शोभा राधेन्द्र यादव, कोचिला शिवदास साकेत, मवई सजन सिंह बघेल, विशुनी टोला पंकज सिंह, कुकडीझर बृजेन्द्र साकेत, कटास रामदास कौल सहित अन्य सरपंच उपस्थित रहे।

विचार

कांग्रेस की गलत नीतियों का परिणाम है देश में आतंकवाद

सुरक्षा बलों ने 4 अक्टूबर को नारायणपुर दंतवाड़ा जिलों की सीमा पर 31 नक्सलियों को मार गिराया। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के 24 साल बाद से किसी एक अभियान में माओवादियों आतंकियों की यह सर्वाधिक मौतों की संख्या है। इस घटना ने देश में आतंकवाद के घाव फिर से हरे कर दिए। देश में हर तरह की आतंकी वारदातें कांग्रेस के केंद्र और राज्यों में सत्ता में रहने के दौरान शुरू हुईं। कांग्रेस की गलत नीतियों से ऐसी रक्तरीजित घटनाओं का परिणाम अभी तक देश भुगत रहा है। आतंकवाद चाहे जम्मू-कश्मीर का हो, नक्सलियों का, पूर्वोत्तर में या फिर पंजाब में खालिस्तान का रहा हो, देश ने कांग्रेस की गलतियों की भारी कीमत चुकाई है। इसी तरह दशकों तक तीन राज्यों में व्याप्त रहा चंबल की बीहड़ों में डकैतों के अपराधों का काला इतिहास भी कांग्रेस के शासन के दौरान लिखा गया। सर्वाधिक आश्चर्य यह है कि कांग्रेस ने इन गलतियों से सबक नहीं लिया। आतंकवाद चाहे जम्मू-कश्मीर में हो या फिर नक्सलियों का हो कांग्रेस ने कभी भी केंद्र की मोदी सरकार की तरह सख्ती नहीं दिखाई। इसके विपरीत कांग्रेस का रवैया वोट बैंक की राजनीति के कारण आतंक समर्थकों के प्रति सहानुभूति का रहा है। लापरवाही और उपेक्षापूर्ण नीतियों के साथ ही राजनीतिक फायदे के लिए की गई आतंकवाद की अवहेलना की कीमत कांग्रेस ने भी चुकाई है। 25 मई 2013 को, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के नक्सली विद्रोहियों ने छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में दरभा घाटी के झीरम घाटी में कांग्रेस नेताओं के काफिले पर हमला किया। इस हमले में कम से कम 27 लोगों की मौत हो गई, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विद्या चरण शुक्ला, पूर्व राज्य मंत्री महेंद्र कर्मा और छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रमुख नंद कुमार पटेल की मौत हो गई। कांग्रेस के केंद्र और राज्यों में शासन के दौरान ही तीनों तरह का आतंक पनपा है। इसमें चंबल में डकैतों का काफी हद तक सफाया हो गया। जम्मू-कश्मीर में पाक परस्त और देश के कुछ राज्यों में नक्सली आतंक अब तेजी सीमित रहा है। केंद्र की भाजपा सरकार दोनों तरह के आतंकियों पर काफी हद तक लगाम लगाने में कामयाब रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक में कहा कि 2026 नक्सलवाद को खत्म कर देंगे। शाह ने कहा कि 30 साल के बाद पहली बार वामपंथी उग्रवाद से मरने वाले लोगों की संख्या 100 से कम रही है। हिंसा की घटनाओं में करीब 53 फीसद की कमी आई है। नक्सली हिंसा से प्रभावित जिलों की संख्या 96 की जगह 42 जिले तक सीमित रह गई है। इन 42 जिलों में से 21 जिले नए बने हैं। इनमें से करीब 16 जिले ही नक्सल हिंसा से प्रभावित हैं। देश की सुरक्षा से संबंधित कांग्रेस की गलत नीतियों का परिणाम सिर्फ देश की आम अवाम को नहीं बल्कि केंद्र की भाजपा सरकार को भी भुगतना पड़ रहा है। केंद्र सरकार को आतंकियों से निपटने के लिए न सिर्फ करोड़ों रुपए बहाने पड़ रहे हैं, बल्कि पुलिस और सुरक्षा बलों को काफी मानवीय क्षति उठानी पड़ी है।

खुली आंखों से समानता के साथ न्याय करने का संदेश

ललित गर्ग

प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़ ने भारतीय न्याय प्रणाली की अनेक विसंगतियों एवं विषमताओं को दूर करते हुए अब न्याय की देवी की मूर्ति की आंखों से काली पट्टी हटा दी गई है। इसके साथ ही मूर्ति की हाथ में तलवार की जगह सविधान ले ली है। यह कानून को सर्वद्रष्टा एवं भारतीयता का रंग देने की एक सार्थक एवं समयोचित पहल है। सांकेतिक रूप से देखा जाए तो कुछ महीने पहले लगी न्याय की देवी की नई मूर्ति साफ संदेश दे रही है कि न्याय अंधा नहीं है और वह सविधान के आधार पर काम करता है। इस सराहनीय कदम के बावजूद एक बड़ा सवाल है कि या मूर्ति की आंखों से पट्टी हटा देने का असर कानूनी प्रक्रिया पर पड़ेगा?



भारत में न्याय प्रणाली पर आम धारणा है कि पुलिस और अदालतें लोगों की जिंदगी को तबाह कर देती हैं, वषों लम्बी न्याय प्रक्रिया झेलने के बाद भी लोगों को समुचित न्याय नहीं मिल पाता है। न्याय में देरी न्याय के सिद्धांत से विमुखता है, न्याय प्राप्त करना और इसे समय से प्राप्त करना किसी भी आदर्श न्याय व्यवस्था में आम व्यक्ति का नैसर्गिक अधिकार होता है। लेकिन यह स्थिति कब बनेगी? क्या न्याय की देवी की मूर्ति में परिवर्तन करने से न्याय प्रक्रिया में कुछ बदलाव हो सकेगा? खुली आंखों से समानता के साथ न्याय करने का संदेश देने वाला यह बदलाव सुप्रीम कोर्ट की जजों की लाइब्रेरी में लगी न्याय की देवी की प्रतिमा में हुआ है। इस प्रतिमा में न्याय की देवी को भारतीय वेषभूषा में दर्शाया गया है। वह साड़ी में दर्शाई गई हैं। सिर पर सुंदर का मुकुट भी है। माथे पर बिंदी, कान और गले में पारंपरिक आभूषण भी नजर आ रहे हैं। जो प्रतीकात्मकता में बदलाव का संकेत है और भारत में न्याय की उभरती भावना को दर्शाता है। लेकिन नई प्रतिमा जिन मूल्यों एवं मानकों की ओर इशारा कर रही है, क्या उसे समझने एवं देखने की हमारी तैयारी है? अगर इस प्रतीकात्मक बदलाव के मूल उद्देश्य को हम नहीं समझ पायेंगे तो यह बदलाव भी अर्थहीन ही होगा। निश्चित ही प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट और न्याय व्यवस्था पारदर्शिता की ओर कदम बढ़ा रही

है। लगातार यह संदेश देने की कोशिश हो रही है कि न्याय सभी के लिए है, न्याय के समक्ष सब बराबर हैं और कानून अब अंधा नहीं है। अब न्याय की देवी के एक हाथ में तराजू और दूसरे हाथ में पुस्तक है जो संविधान जैसी दिखती है। यह सर्वविदित एवं लोगों में आम धारणा है कि थाना-पुलिस और कोर्ट-कचहरी का चक्र लगा-लगा कर आम आदमी की जिंदगी तबाह हो रही है, तब मूर्ति की आंखों से पट्टी हटाकर भला क्या सुधार जाना है? न्याय की देवी को सच में आंखें देनी हैं तो कानून में आमूल-चूल परिवर्तन, त्वरिता, समयबद्धता एवं समानता की जरूरत होगी। यह तो चीफ जस्टिस भी जानते हैं। आखिर किसे नहीं पता कि इस देश में सड़क से लेकर अदालत तक, हर जगह कानून की धज्जियां उड़ती हैं और न्याय की देवी यू ही स्टैच्यू बनी रहती हैं। कोई हरकत नहीं, बिल्कुल संवेदनहीन। सड़कों पर कानून तमाशाबान बनकर खड़ा है, थाने में वह उगाही और उपपीड़न का अस्त्र बना है तो अदालतों में दलीलों और तारीखों की बेइतहा ऊबाऊ प्रक्रिया का जटिल हिस्सा है, जिसकी जकड़न में गए तो खेर नहीं। अब तक अंधे कानून की त्रासदी न्याय की देवी देख नहीं पाती थीं, अब वो खुली आंखों से सब देखेंगी। कम-से-कम उम्मीद तो कर ही सकते हैं कि देख पाने के कारण न्याय की देवी की मूर्ति में भी संवेदना जग जाए। जस्टिस चंद्रचूड़ ने वाकई अच्छी

पहल की है, उसका स्वागत होना चाहिए।

1983 को एक फिल्म अंधा कानून रिलीज हुई थी। इस फिल्म एवं इसके गाने में कोर्ट-कचहरी, चकोल-दलील, सुनवाई-फैसले के हालात को शब्द दिए गये हैं। कहा गया कि अस्मत्तें लुटें, चली गोली, इसने आंख नहीं खोली। फिर गीत कहता है- लंबे इसके हाथ सही, ताकत इसके साथ सही। पर ये देख नहीं सकता, ये बिन देखे है लिखता। इस तरह फिल्म कानून को अंधा बताती है। स्थिति यह है कि आज भी न्यायालयों में यह चर्चा अमूमन होती है कि अदालत में पेश होने वाले अभियोजन या अभियोग पक्ष के रुतबे को देखकर न्याय प्रभावित हो जाता है। लेकिन उस समय की मूर्ति की मूल भावना कहां और कितनी प्रभावी रही है, यह सर्वविदित है। अब नयी संशोधित प्रतिमा का संदेश है कि देश में न्याय अंधा नहीं है, वह इस बात पर जोर देती है कि भारत में न्याय दूरदर्शिता और समानता के साथ काम करता है। जो संतुलन और निष्पक्षता का प्रतीक है-यह दर्शाता है कि न्यायालय किसी निर्णय पर पहुँचने से पहले सभी पक्षों से तथ्यों और तर्कों को तौलता है। इसका मतलब है कि कानून को नजर में सभी बराबर हैं, इसमें न पैसे वाले का महत्व, न रुतबा, ताकत और हैसियत को महत्व दिया जाता है।

न्याय की देवी, जिसे हम अक्सर अदालतों में देखते हैं, असल में यूनान की देवी हैं। उनका नाम जस्टिसा है और उन्हीं के नाम से 'जस्टिस' शब्द आया है। उनकी आंखों पर बंधी पट्टी दिखाती है कि न्याय हमेशा निष्पक्ष होना चाहिए। 17वीं शताब्दी में एक अंग्रेज अफसर पहली बार इस मूर्ति को भारत लाए थे। यह अफसर एक न्यायालय अधिकारी थे। 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश राज के दौरान न्याय की देवी की मूर्ति का सार्वजनिक रूप से इस्तेमाल होने लगा। भारत की आजादी के बाद भी हमने इस प्रतीक को अपनाया। यह बदलाव औपनिवेशिक शासन के अवशेषों को हटाने के अन्य प्रयासों को दर्शाता है, भारत गुलामी के सभी संकेतों से बाहर निकलना चाहता है। जैसे कि हाल ही में आपराधिक कानूनों में बदलाव, भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता को लागू करना है।

यहां नई मूर्ति के नए संकेतों का अर्थ गहराई से समझना भी जरूरी है। न्याय समाज में संतुलन का प्रतिनिधित्व करें, न्यायिक संचालन-प्रक्रिया सांविधानिक प्रावधानों के अनुरूप चले। सबको समान रूप से देखें। हम न्याय की देवी द्वारा इंगित मूल्यों में संजीदगी दिखाएँ। हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि आखिर भारतीय न्याय-व्यवस्था को लेकर आम धारणा इतनी कटु क्यों है? यह क्यों माना जाता है कि यहां न्याय देर से मिलता है, जबकि अदालतों में तारीखें अनवरत मिलती रहती हैं? जिस सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की वकालत की गई है, उसे वास्तविक अर्थों में साकार करने में हम अब तक क्यों विफल रहे हैं? जब तक इन सवालों के उचित जवाब हम नहीं खोज लेते हैं, तब तक न्याय की देवी के प्रतीक-चिह्नों की सार्थकता कठघरे में खड़ी की जाती रहेगी। असल में, प्रतीक-चिह्न एक पहचान के रूप में काम करते हैं। इन प्रतीक-चिह्नों से जो प्रतीकात्मक अर्थ निकल रहा है, वह हर हाल में साकार हो। भारतीय अदालतें इस मामले में उम्मीदों पर पूरी तरह खरी नहीं उतर सकी हैं। लिहाजा, इन संकेतों के सार्थक होने के लिए हमें कुछ अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। न्याय में देर करना अन्याय है। भारत की न्यायप्रणाली इस मायने में अन्यायपूर्ण कही जा सकती है, क्योंकि भारत की जेलों में 76 प्रतिशत कैदी ऐसे हैं, जिनका अपराध अभी तय नहीं हुआ है और वे दो दशक से अधिक समय से जेलों में नारकीय जीवन जीते हुए न्याय होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए न्यायप्रणाली की धीमी रफ्तार को गति देकर ही ऐसे विचाराधीन कैदियों के साथ न्याय देना संभव है और इसी से सशक्त भारत का निर्माण होगा और प्रतीकात्मक प्रतीक चिह्नों में बदलाव का कोई सार्थक उपयोग एवं असर होगा। भारत को अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक परिस्थिति और अपने गौरवपूर्ण इतिहास बोध के अनुसार एक वैकल्पिक न्याय तंत्र भी स्थापित करना चाहिए, किंतु जब तक यह नहीं होता वर्तमान व्यवस्था में ही कुछ आवश्यक सुधार करके हमें इसे समसामयिक, तीक्ष्ण, समयबद्ध और उपयोगी बनाए रखना चाहिए। न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिये बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिये। भारत की सम्पूर्ण न्याय व्यवस्था का भारतीयकरण होना चाहिए।

रबी फसलों के एमएसपी की घोषणा, बाजारी ताकतों पर नियंत्रण जरूरी

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा

बुवाई से पहले या बुवाई के समय फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा इस मायने में महत्वपूर्ण हो जाती है कि किसानों को कौन सी फसल लेना लाभकारी रहेगा इस पर सोच विचार कर निर्णय करने का अवसर मिल जाता है। पिछले कुछ सालों से केंद्र सरकार द्वारा खरीद हो या रबी लगभग इनके बुवाई के समय ही न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कर दी जाती है। इस सरकार की सकारात्मक पहल भी कहा जा सकता है। केंद्र सरकार ने रबी सीजन की गेहूं, सरसों सहित छह प्रमुख फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है। एमएसपी की घोषणा करते समय यह भी दावा किया गया है कि इन सभी छहों फसलों के एमएसपी का निर्धारण लागत से अधिक किया गया है जिससे किसानों के लिए यह फसलें लाभकारी सिद्ध हो सके। दावों की माने तो लागत की तुलना में सर्वाधिक 105 प्रतिशत अधिक एमएसपी गेहूं की घोषित की गई है, सबसे कम कुसुम की लागत से 50 प्रतिशत अधिक है तो चना और जौ की लागत से 60 फीसदी अधिक घोषित की गई है। सरसों की लागत से 98 फीसदी तो मसूर की 89 प्रतिशत अधिक राशि तय की गई है। निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि लागत की तुलना में सभी छह फसलों की एमएसपी दरों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की गई है। एमएसपी की घोषणा करते समय सरकार ने लागत में खाद-बीज, क्रोटाशाक, सिंचाई पर व्यय के साथ ही मानव श्रम का भी समावेश किया गया है। ऐसे में लागत से अधिक राशि मिलना किसानों के लिए लाभकारी हो सकता है।

देश में 1966-67 में सबसे पहले गेहूं की

सरकारी खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की गई थी। आज से लगभग 60 साल पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने एक अगस्त 1964 को एलके झा की अध्यक्षता में इसके लिए कमिटी घटित की थी। गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीद व्यवस्था का एक विपरीत प्रभाव सामने आने पर कि किसान अन्य फसलों की जगह गेहूं की फसल पर ही केन्द्रित होने लगे तो ऐसी स्थिति में सरकार ने अन्य प्रमुख फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के दायरों में लाया गया। कृषि मूल्य एवं लागत आयोग की सिफारिश पर कृषि जिनसे के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। देश में गेहूं, धान आदि 7 अनाज फसलें, 5 दलहन, 7 तिलहन, 4 नकदी फसलों के समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। नकदी फसलों में गन्ना के सरकारी खरीद मूल्य की गन्ना आयोग द्वारा की जाती है तो गन्ने की खरीद भी गन्ना मिलों द्वारा की जाती है। इसी तरह से कपास की खरीद सीसीआई यानी कि कॉटन कारपोरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा की जाती है।

केंद्र सरकार द्वारा प्रमुखतः राज्यों में सहकारी संस्थाओं के नेटवर्क के माध्यम से एमएसपी की खरीद की जाती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि देश में सहकारी संस्थाओं का विस्तृत और सीधे काश्तकारों की पहुंच का नेटवर्क है। अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और फिर खरीद के बाद ऑनलाइन भुगतान व्यवस्था से पारदर्शिता आई है। पर सवाल अभी वही है कि जब तक बाजार में खासतौर से मण्डियों में एमएसपी फसलों के भाव घोषित एमएसपी दरों के समकक्ष नहीं आते तब तक खरीद जारी रहने से ही काश्तकारों को सही मायने में इस व्यवस्था का फायदा मिल सकता है।



दुर्भाग्य की बात यह है कि पारदर्शी व्यवस्था में भी बिचौलियों ने सेंध लगा ली है और लाख प्रयासों के बावजूद छोटे किसानों को सब तो नहीं पर कुछ काश्तकारों को व्यवस्था का लाभ नहीं मिल पाता। इसमें व्यवस्था का दोष इस मायने में है कि किसान को अपनी तात्कालिक व आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए साहूकार पर निर्भर रहना पड़ता है, ऐसे में काश्तकार अपनी फसल काश्तकार के नाम कर उससे अग्रिम राशि ले लेता है और बदले में काश्तकार के दस्तावेज से बिचौलियों लाभ उठा लेते हैं।

यह तो साफ है कि गेहूं और धान की खरीद

सरकार द्वारा व्यापक स्तर पर की जाती रही है और इसका प्रमुख कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरण व्यवस्था के सुचारु संचालन और बाजार पर नियंत्रण रखना रहा है। अन्य फसलों का जहां तक सवाल है देश के अधिकांश प्रदेशों में खाद्यान्नों की खरीद एफसीआई द्वारा राज्यों के मार्केटिंग फेडरेशनों के माध्यम से सहकारी संस्थाओं द्वारा व तिलहनों और दलहनों की खरीद नैफेड द्वारा भी इसी व्यवस्था के तहत किया जाता रहा है। एक समय था जब न्यूनतम खरीद आरंभ होते ही मण्डियों में भी भावों में तेजी आने लगती थी। पर अब ऐसा नहीं हो रहा है इसके कारण क्या है,

इस पर विचार करना।

दरअसल बिचौलियों ने एमएसपी खरीद व्यवस्था में सेंध लगा दी है। किसान से ही खरीद और ऑनलाइन व्यवस्था के बावजूद इस व्यवस्था का लाभ बिचौलियों अधिक उठाने लगे हैं। सवाल यह है कि केंद्र व राज्य सरकारें एमएसपी व्यवस्था को फूलफूल बनाना सुनिश्चित कर दें और सरकार द्वारा घोषित एमएसपी से मण्डियों में भाव नीचे जाते ही तत्काल खरीद आरंभ हो जाए तो निश्चित रूप से अन्नदाता को इस व्यवस्था का पूरा पूरा लाभ मिल सकता है। इसके साथ ही इस व्यवस्था में जिस तरह से सेंध लगाई गई है उसे रोकने के भी ठोस प्रयास किए जाने आवश्यक है। कहीं ना कहीं एक बार फिर से बाजार व्यवस्था का भी अध्ययन करना होगा। क्यों खरीद बंद होने के कुछ समय बाद ही जिनसे के भाव बढ़ने लगते हैं। हाल ही में गेहूं के भावों में बढ़ोतरी और हर साल एक समय विशेष पर आलू, प्याज, टमाटर के भाव का बढ़ जाना कहीं ना कहीं यह बताता है कि कमोबेस बाजार ताकतें अधिक शक्तिशाली हैं और वे ही डोमिनेट करती हैं।

इसलिए एक और जहां एमएसपी की खरीद व्यवस्था में सुधार व किसानों को ही वास्तविक लाभ मिले इससे प्रयास करने की आवश्यकता है उसी तरह से बाजार की ताकतों पर भी नजर रखना जरूरी हो जाता है ताकि एक और तो काश्तकार को ठगा महसूस करने से बचाया जा सके और आम नागरिक भी ठगा हुआ महसूस ना कर सके। कहीं ना कहीं बाजार पर सरकार के नियंत्रण की आवश्यकता है नाकि बाजार ताकतों के हाथ में छोड़ने की। ऐसा होने पर ही सही मायने में एमएसपी व्यवस्था का लाभ मिल सकेगा।

मणिपुर में उग्रवादियों ने गांव पर बम फेंके

इम्फाल (एजेंसी)। मणिपुर के जिरिबाम जिले में एक बार फिर हिंसा भड़की है। बोरोबेकरा इलाके के एक गांव में उग्रवादियों ने शनिवार सुबह 5 बजे फायरिंग कर दी। बोरोबेकरा पुलिस ने बताया कि उग्रवादियों ने गांव में बम भी फेंके हैं। सूचना मिलने पर पुलिस और सीआरपीएफ की टीमों मौके पर पहुंची हैं। उग्रवादियों और सुरक्षाबलों के बीच फायरिंग लगातार जारी है। फिलहाल हमले में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। पुलिस ने बताया कि बोरोबेकरा जिरिबाम टाउन से 30 किमी दूर है। इस इलाके में घने जंगल और पहाड़ हैं और यहां पहले भी गोलीबारी जैसी घटनाएं हो चुकी हैं। इससे पहले 18 अक्टूबर को जिरिबाम के ही कालीनगर हमार वेंग इलाके में उग्रवादियों ने एक स्कूल में आग लगा दी थी। 15 अक्टूबर को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्रालय की निमंत्रण पर मैतेई, कुकी और नगा समुदायों के 20 विधायक दिल्ली पहुंचे थे। इन्हें मणिपुर और हिंसा न होने का संकल्प दिलाया गया था। बैठक के 4 दिन बाद शनिवार को जिरिबाम में हिंसा हुई है। 4 दिन पहले मणिपुर में शांति के लिए दिल्ली में बैठक हुई थी 15 अक्टूबर को हुई बैठक में पहले कुकी, फिर मैतेई और बाद में नगा नेताओं से बात की गई। सभी ने अपनी-अपनी मांगों केन्द्र के सामने रखीं। इसके बाद सभी को एक हॉल में इकट्ठा कर संकल्प दिलाया गया कि आज की बैठक के बाद मणिपुर में न तो एक भी गोली चलेगी और न ही किसी व्यक्ति की जान जाएगी। तीनों समुदायों के प्रतिनिधियों ने इस पर सहमति दी। इसके बाद प्रतिनिधियों ने एक-दूसरे से हाथ मिलाए। सूत्रों के मुताबिक करीब डेढ़ घंटे चली बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मणिपुर के सीएम एन. बीरेन सिंह मौजूद नहीं थे, लेकिन शाह बैठक को मिनट-टू-मिनट मॉनिटरिंग कर रहे थे।

जम्मू-कश्मीर के पुंछ में 2 आतंकी गिरफ्तार

श्रीनगर (एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर के पुंछ में शनिवार सुबह सुरक्षाबलों ने 2 आतंकी को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 3 ग्रेनेड और 1 पिस्तौल भी बरामद की गई है। सेना के अधिकारियों ने बताया ये दोनों जम्मू-कश्मीर गजनावी फोर्स नाम के संगठन से जुड़े हाइब्रिड आतंकी हैं। हाइब्रिड आतंकी आम नागरिकों की तरह ही इलाके में रहते हैं, लेकिन चोरी-छिपे आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होते हैं या आतंकीयों की सहायता करते हैं। इन्हें पहचानना मुश्किल हो जाता है। जम्मू पुलिस के एडीजीपी आनंद जैन ने कहा कि पुंछलाह में पता चला कि दोनों आतंकी ने मंदिर, सेना के ठिकानों और एक अस्पताल पर ग्रेनेड फेंकने की प्लानिंग कर रहे थे। वे लोगों में डर पैदा करने के लिए पुंछ में एंटी नेशनल पोस्टर भी चिपकाते थे। ये आतंकी बॉर्डर के पार पाकिस्तान में बैठे आतंकीयों के संपर्क में थे। पुलिस ने 27 सितंबर को पुलवामा के अवंतीपोरा में टैरर मॉड्यूल का खुलासा किया। पुलिस ने जैश-ए-मोहम्मद के 6 आतंकी सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। ये युवाओं को आतंकवाद की ट्रेनिंग देते थे।

राज्यपाल की मौजूदगी में तमिलगान में द्रविड़ शब्द छूटा

चेन्नई (एजेंसी)। तमिलनाडु में राज्यपाल आरएन रवि और एरुएमके स्टालिन के बीच एक बार फिर विवाद हो गया है। इस बार मामला तमिलगान से द्रविड़ शब्द हटवाने के आरोप से जुड़ा है। जिसके बाद सीएम ने पीएम मोदी से राज्यपाल को हटाए जाने की मांग की है। एरुएमके उन्हें आर्यन कहा। उन पर देश और तमिलनाडु की एकता का अपमान करने का आरोप भी लगाया।

समृद्धि योजना अंतर्गत समग्र ग्राम विकास के विभिन्न आयाम विषय पर जन अभियान परिषद की कार्यशाला हुई: मुख्यमंत्री

भोपाल (एजेंसी)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि जन अभियान परिषद जन-जन के कल्याण के लिए समर्पित है। स्वैच्छिक, सामूहिक और सामुदायिक सहभागिता से स्वावलंबन के दृष्टिकोण से पूर्व केंद्रीय मंत्री स्व. अनिल माधव दत्ते ने प्रत्येक प्रदेशवासी को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से परिषद के गठन की प्रेरणा दी थी। सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर समाज भी चले इस उद्देश्य से जन अभियान परिषद को एक कड़ी के रूप में विकसित किया गया। शासकीय योजनाओं को जन-जन तक ले जाने में जन अभियान परिषद उत्तरेक की भूमिका निभा रही है। परिषद भू-जल भण्डारण सहित समाज कल्याण और विकास गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव समन्वय भवन में समृद्धि योजना अंतर्गत समग्र ग्राम विकास के विभिन्न आयाम विषय पर



मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा राज्य, संभाग और जिला स्तरीय समन्वयकों के उन्मुखीकरण सह-प्रशिक्षण कार्यशाला के शुभारंभ अवसर पर संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा, परिषद के उपाध्यक्ष श्री मोहन नागर, प्रमुख सचिव श्री संजय कुमार शुक्ला उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण ने संस्कृति में आ रही विकृतियों से संघर्ष के कई प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत किए। साथ ही कंस रूपी बुराई से संघर्ष के लिए स्त्री-पुरुषों के साथ बच्चों को भी संगठित कर समाज की संगठन क्षमता और जन-कल्याण के लिए उसके सार्थक उपयोग का संदेश दिया। यह दर्शाता है कि संगठन की शक्ति से बड़ी चुनौतियों का सामना किया जा सकता है।

जम्मू-कश्मीर को स्टेटहुड के प्रस्ताव को एलजी की मंजूरी

श्रीनगर (एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के प्रस्ताव को उपराज्यपाल ने शनिवार को मंजूरी दे दी। गुरुवार को राज्य के दर्जा की बहाली के लिए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट ने प्रस्ताव पास किया था। डिप्टी सीएम सुरिंदर कुमार चौधरी ने कहा, केंद्र को अपना वादा पूरा करना चाहिए और राज्य का दर्जा बहाल करना चाहिए, यह हमारा अधिकार है। हम वही मांग रहे हैं जो उन्होंने पहले ही वादा किया था। इस मांग को लेकर उमर अब्दुल्ला 2 दिन में दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। दरअसल, केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के साथ ही प्रदेश का पूर्ण राज्य का दर्जा खत्म करते हुए उसे दो यूनिनियन टेरिटरी (जम्मू-कश्मीर और लद्दाख) में



बांट दिया था। उमर ने विधानसभा चुनाव के दौरान भी कहा था कि कैबिनेट की पहली मीटिंग में ही जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दिया जाएगा। 16 अक्टूबर को सीएम पद की शपथ लेने के बाद अगले दिन ही उन्होंने प्रस्ताव पास किया। कैबिनेट की मीटिंग में डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी, मंत्री सकीना मसूद इट्ट, जावेद अहमद

झारखंड चुनाव, भाजपा की पहली लिस्ट में 66 नाम

रांची (एजेंसी)। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने शनिवार शाम 66 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता रहे पूर्व सीएम चंपाई सोरेन को सरायकेला से उम्मीदवार बनाया गया है। चंपाई ने इसी साल अगस्त में पार्टी छोड़ी थी। इसके अलावा झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा और अर्जुन मुंडा की पत्नियों को भी टिकट दिया गया है। मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा को जगन्नाथपुर से, अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा को धनवार से और सीएम हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन को जामताड़ा से टिकट दिया गया है। झारखंड में एनडीए के अंदर बीजेपी-68, आजसू-10, जेडीयू-2 और लोजपा रामविलास 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को जमशेदपुर पश्चिम और



तमाड़ सीट दी गई है। चिराम पासवान के एलजेपी (रामविलास) को चतरा सीट मिली है। झारखंड में 13 नवंबर को पहले चरण का मतदान होगा। इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। पहले चरण के लिए 25 अक्टूबर तक नामांकन प्रक्रिया चलेगी। इसके बाद 28 अक्टूबर को पर्चे की स्क्रूटनी की जाएगी। 30 अक्टूबर तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकते हैं। वहीं दूसरे चरण के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा। इसके लिए 22 अक्टूबर को अधिसूचना जारी की जाएगी। नामांकन की आखिरी तारीख 29 अक्टूबर होगी। दूसरे चरण में 20 नवंबर को मतदान होगा। इसके लिए 30 अक्टूबर को पर्चे की स्क्रूटनी की जाएगी। 1 नवंबर तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकते हैं। 23 नवंबर को मतदान होगा। झारखंड विधानसभा में 81 सीटें हैं। इनमें 44 अनारक्षित, 28 एसटी और 09 एससी के लिए सुरक्षित सीटें हैं।

राहुल गांधी बोले- 50 प्रतिशत आरक्षण को हम तोड़ देंगे



रांची। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को रांची के शौर्य सभागार में संबिधान सम्मान सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा- जब भाजपा के लोग आदिवासी को वनवासी कहते हैं तो वे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? आपका जो

में रहते हैं। जब इस शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वो केवल एक शब्द नहीं होता। ये आपका पूरा इतिहास है। मैं हिंदुस्तान की शिक्षा व्यवस्था में पढ़ा हूँ। आदिवासियों के बारे में केवल 10-15 लाइनें ही मिलेंगी। इनका इतिहास क्या है, जीने का तरीका क्या है। उस बारे में कुछ नहीं लिखा। आपके बारे में जेएमएम शब्द प्रयोग किया गया। क्या ये आपका नाम है? किसने कहा आप पिछड़े हो? आपका जो हक है वो आपको नहीं दिया जाता। जिन लोगों ने इस देश को बनाया है किसान, मजदूर, बर्दई, नाई, मोची का इतिहास कहा है। किसान और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर सहमति बन गई है। सीएम हेमंत सोरेन और

सीजेआई बोले- सुप्रीम कोर्ट को लोगों की अदालत बनाया

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने शनिवार को कहा कि मैंने सुप्रीम कोर्ट को लोगों की अदालत बनाने की कोशिश की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम संसद में विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। सीजेआई ने ये बात द सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन के पहले अंतरराष्ट्रीय कानून सम्मेलन में कही। सीजेआई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का दायित्व संसद में विपक्ष के रूप में कार्य करना नहीं है। कानूनी विमंगतियों लिए कोर्ट की आलोचना स्वीकार है, लेकिन इसकी भूमिका और काम का मूल्यांकन केस के फैसलों के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने टेक्नोलॉजी का उपयोग करके और कई



प्रक्रियाओं को आसान किया है, लेकिन मैं जानता हूँ कि चाहे कितने भी सकारात्मक फैसले लिए जाएं, संस्था की तरफ से ईकोसिस्टम पर निर्भर करती है, जिसमें सभी योगदान करते हैं। एससीएओआरए की जिम्मेदारी मुवक्किल-कोर्ट के बीच की खाई कम हो सीजेआई ने कहा कि एससीएओआरए का

प्राइमरी काम यह सुनिश्चित करना है कि उनके काम के जरिए कोर्ट न्याय दे सके। यह सुनिश्चित करना आपकी जिम्मेदारी है कि मामला ठीक से तैयार हो, अच्छी तरह से समझाया जाए और याचिका बिना गलती के दायर की जाए। आपकी जिम्मेदारी है कि मुवक्किल और कोर्ट के बीच की खाई कम हो। सुप्रीम कोर्ट में अधिकतर पिटीशनर के पास अपने मामलों पर समय पर अपडेट के लिए अपने एससीएओआरए के अलावा कोई नहीं होता है। उन्होंने कहा कि मैं सभी से आग्रह करता हूँ कि अपने जूनियर के प्रति भी शिष्टाचार बरतें। आखिरकार कानूनी पेशे का विकास जूनियर्स के वेलफेयर और डेवलपमेंट से जुड़ा है।

राजनाथ बोले- एआई से मिलिट्री ऑपरेशन में क्रांति की क्षमता

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मिलिट्री ऑपरेशन में क्रांति लाने की क्षमता है। दुःखद है कि अनुमान लगाकर विश्लेषण कर सकता है। उसके पास स्वतंत्र डिजिटल मैकिंग सिस्टम भी है। राजनाथ सिंह शनिवार को दिल्ली में आयोजित 62वें राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय पाठ्यक्रम दोक्षांत समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप (जनता) लीडर होंगे, जिन्हें ये तय करना होगा कि इस तकनीक का फायदा कहां और कैसे उठाया जाए। आज की परस्पर जुड़ी दुनिया में मिलिट्री लीडर्स को जियो-पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन और ग्लोबल सिक्वोरिटी अलायंस की परेशानियों को मजबूत समझ होना बहुत जरूरी है। सिंह ने कहा कि मिलिट्री

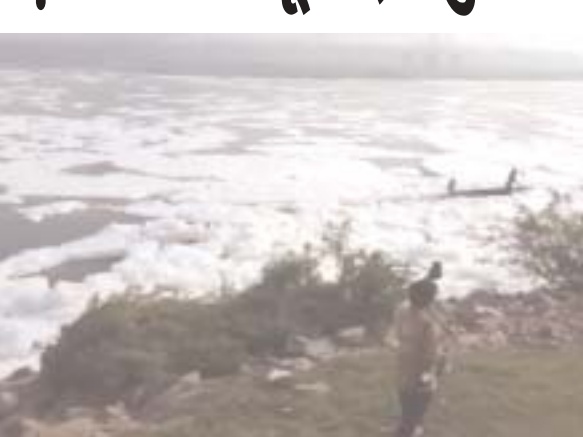


लीडर्स के लिए गैर फैसलों के दूरगामी रिजल्ट हो सकते हैं, जो युद्ध के मैदान से आगे बढ़कर डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल लॉ के दायरे में भी फैल सकते हैं। ऐसे में इन क्षेत्रों में पॉलिटिकल सीख बहुत जरूरी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि ये सोचना कि हमारे विरोधी इन क्षमताओं का फायदा उठा

सकते हैं, इस बात को याद दिलाता है कि हमें ऐसी किसी भी संभावित संभावना के लिए कितनी तत्परता से तैयारी करनी चाहिए। भारतीय सेना दुनिया में चौथी सबसे ताकतवर, पाकिस्तान 9वें नंबर पर फरवरी 2024 में सेना संबंधी डेटा रखने वाली वेबसाइट ग्लोबल फायरपावर की 'सैन्य ताकत सूची-2024' में दुनिया के 145 देशों की सेनाओं की क्षमताओं का एनालिसिस कर रैंकिंग जारी की थी। इसके मुताबिक, भारत को पास दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना है। अमेरिका सैन्य क्षमता के मामले में सबसे शक्तिशाली देश है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर रूस और तीसरे पर चीन का नाम था। लिस्ट में 60 से ज्यादा पैमानों के आधार पर रैंकिंग की गई थी।

दिल्ली में फिर बढ़ा एयर पॉल्यूशन, यमुना में जहरीला झाग

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली-एनसीआर में शनिवार सुबह एयर क्वालिटी में काफी गिरावट देखी गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 पॉइंट को पार कर गया। सुबह आसमान में धुंध छाई रही और लोगों को सांस लेने में भी परेशानी महसूस हुई। उधर, यमुना नदी में जहरीला झाग लगातार दूसरे दिन भी नजर आ रहा है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि सटीक बढ़ने की वजह से दिल्ली-एनसीआर की एयर क्वालिटी खराब हो रही है। दो दिन से पॉल्यूशन का स्तर बढ़ रहा है। इससे लोगों को गले में दर्द, सांस लेने में दिक्कत और आंखों में जलन हो रही है।



इसी के साथ त्वचा से जुड़ी बीमारियां होने का भी खतरा बढ़ जाता है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने पॉल्यूशन को लेकर 18 अक्टूबर को इमरजेंसी मीटिंग की थी। उन्होंने कहा कि कुल 13 हॉटस्पॉट हैं, जहां एक्वआई 300 को पार कर गया है। मंत्री ने अधिकारियों को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए और कहा- पॉल्यूशन इतना ज्यादा क्यों हो रहा है, इसकी

वजह पता करें। यमुना नदी के जहरीले झाग दिखाई दे रहा है। एक्सपर्ट का कहना है कि इसमें अमोनिया और फॉस्फेट की मात्रा बहुत ज्यादा है। इससे स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। छठ पूजा जैसे प्रमुख त्योहार नजदीक आ रहे हैं। इस दौरान जहरीले झाग की वजह से दूषित हो सकती है। इसे लेकर दिल्ली जल बोर्ड ने मीटिंग की है। जल बोर्ड छठ पूजा के पहले झाग को हटाना चाहता है। दरअसल, हर साल ओखला के कालिंदी कुंज में बैराज पर छठ पूजा के दौरान नदी में डुबकी लगाने के लिए सैकड़ों भक्त आते हैं। बैठक में भाग लेने वाले एक अधिकारी ने दावा किया।

